卐 श्री सदगुरू देवाय नमः 卐 卐 ओ३म् 卐 卐 जय माता दी 卐
卐 सीताराम बाबा जी 卐卐 जय बाबा की 卐卐 श्याम बाबा 卐卐
卐 ! जाके सुमिरन तें रिपु नासा!! ! नाम सत्रुहन बेद प्रकासा!! 卐

उल्लंघ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं,यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः। आदाय तेनैव ददाह लंकां,नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्।
मनोजवं मारुत तुल्य वेगं,जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये।

केन्द्र व उत्तरांचल सरकार से विज्ञापन मान्यता प्राप्त

हिन्दी सान्ध्य दैनिक

उत्तरांचल दर्पण

♦वर्ष 26 ♦अंक 153 ♦पृष्ठ 8 ♦रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) ♦बुधवार ♦11 मार्च 2026 ♦मूल्य दो रूपया

darpan.rdr@gmail.com 9897427585 UTTARANCHAL DARPAN www.uttaranchaldarpan.in

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति

नई दिल्ली (उद संवाददाता)। भारतीय न्यायिक इतिहास में आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील अध्याय जुड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में पहली बार 'पैसिव यूथेनेशिया' (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) को वास्तव में लागू करने की मंजूरी प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने गाजियाबाद के 32 वर्षीय युवक हरीश राणा के मामले में यह ऐतिहासिक आदेश दिया, जो पिछले 13 वर्षों से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट (स्थायी अचेत अवस्था) में केवल मशीनों और ट्यूबों के सहारे जी रहा था। कोर्ट ने हरीश के पिता की उस मर्मस्पर्शी गुहार को

स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को इस असहनीय कष्ट से मुक्ति दिलाने की मांग की थी। यह फैसला वर्ष 2018 के प्रसिद्ध 'कॉमन कॉज' जजमेंट पर आधारित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 'गरिमा के साथ मरने' को मनुष्य के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। हरीश राणा की यह कहानी किसी भी संवेदनशील हृदय को झकझोर देने वाली है। वर्ष 2013 में चंडीगढ़ में एक पेइंग गेस्ट हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के कारण उसे गंभीर ब्रेन इंजरी हुई थी, जिसने एक हंसते-खेलते युवक की जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। पिछले 13 वर्षों से वह पूरी तरह बिस्तर पर था और उसका शरीर 100 फीसदी क्वाड्रिप्लेजिक हो चुका था। वह केवल ट्रेकियोस्टॉमी ट्यूब के माध्यम से सांस ले पा रहा था और (शेष पृष्ठ सात पर)

गैरसैंण स्थाई राजधानी के लिए जोरदार प्रदर्शन

गैरसैंण(उद संवाददाता)। गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थाई राजधानी घोषित करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। इसी क्रम में बुधवार को सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह के साथ विधानसभा कूच का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने दिवालीखाल के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा और घेराबंदी के कारण प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ पाए, जिसके विरोध में उन्होंने सड़क पर ही बैठकर जोरदार प्रदर्शन और धरना दिया। सुराज सेवा दल के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य बने इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी गैरसैंण को लेकर जनता को केवल गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और स्थाई राजधानी पर अनिर्णय की स्थिति के कारण पलायन का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसे रोकने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक गैरसैंण को पूर्ण रूप से स्थाई राजधानी का दर्जा नहीं मिलता, उनका संघर्ष और आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। दूसरी ओर हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों और (शेष पृष्ठ सात पर)

जंगल में महिला का शव मिलने से सनसनी

देहरादून (उद संवाददाता)। राजधानी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मांडूवाला के जंगलों में बुधवार को एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जंगल में महिला का शव पड़े होने की सूचना जैसे ही स्थानीय लोगों को मिली, देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुँचकर जांच-पड़ताल शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार को कुछ लोग मांडूवाला के जंगल की ओर गए थे, जहाँ उन्होंने एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा देखा। सूचना मिलते ही प्रेमनगर थाना पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम घटनास्थल पर पहुँची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। खबर लिखे जाने तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में (शेष पृष्ठ सात पर)

सत्र के तीसरे दिन तीखे सवालों से गरमाया माहौल

भराड़ीसैंण (उद संवाददाता)। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही विपक्ष विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर हो गया, जिससे सदन का माहौल गरमा गया। कांग्रेस विधायकों ने नियम 310 के अंतर्गत प्रदेश में भूमिधरी के अधिकार से जुड़े संवेदनशील मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और सरकार से इस पर स्पष्टीकरण की मांग की। विपक्ष के तीखे तेवरों के कारण सदन के भीतर काफी देर तक नोकझोंक की स्थिति बनी रही। सदन के भीतर चल रही गहमागहमी के बीच बाहर भी विरोध के स्वर सुनाई दिए। हल्द्वानी से कांग्रेस विध

ायक सुमित हृदयेश अपनी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों और लंबित मुद्दों की अनदेखी को लेकर विधानसभा भवन परिसर में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनसमस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। वहीं, सदन के भीतर प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई तीखे सवाल सत्ता पक्ष के सामने रखे गए, जिनका जवाब देने में मंत्रियों को काफी मशक्कत करनी(शेष पृष्ठ सात पर)

तलवार की नोंक पर बाईक लूटी

सितारगंज। पेट्रोल पंप जा रहे बाइक सवार युवक की गर्दन पर तलवार रख दो युवकों ने बाइक लूट ली। पुलिस ने मामले में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम (शेष पृष्ठ सात पर)

आवश्यकता है

एक जीएसटी अनुभवी एकाउन्टेंट की।
-सम्पर्क करें-
मोबाईल नम्बर
9548200711
8218640588

खाड़ी युद्ध की तपिश: गैस सिलेंडरों के लिए मचा हाहाकार

25 दिन की पाबंदी और कालाबाजारी के डर ने बढ़ाई उपभोक्ताओं की धड़कनें, एजेंसियों पर लंबी कतारें

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। विश्व के खाड़ी देशों में छिड़े भीषण युद्ध की आंच अब भारतीय रसोई और औद्योगिक विकास तक पहुंचनी शुरू हो गई है। पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने का सीधा असर अब आम आदमी की जेब और दैनिक जीवन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे

रहा है। केंद्र सरकार भले ही देश में पर्याप्त भंडार होने के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हालत यह है कि कल तक जो सिलेंडर एक फोन कॉल पर घर पहुंच जाता था, उसके लिए आज उपभोक्ताओं को कड़ाके की ठंड और अनिश्चितता के बीच पसीने बहाने पड़ रहे हैं। गैस आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने जो कड़े कदम उठाए हैं, उन्होंने आम जनता की मुश्किलों को दोगुना (शेष पृष्ठ 7 पर)

प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील

रूद्रपुर। प्रशासन और गैस वितरकों ने इस चुनौतीपूर्ण समय में आम जनता से धैर्य रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि गैस की गाड़ियों की आवक में तकनीकी देरी जरूर हो रही है, लेकिन आपूर्ति को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे घबराकर गैस का अनावश्यक भंडारण न (शेष पृष्ठ सात पर)

होटल-रेस्टोरेंट कारोबार प्रभावित

रूद्रपुर। घरेलू गैस के साथ-साथ व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में आई भारी गिरावट ने व्यापार जगत की कमर तोड़कर रख दी है। कुमाऊं क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और छोटे भोजनालयों के सामने गैस का संकट खड़ा हो गया है। गैस एजेंसियों के पास कमर्शियल सिलेंडरों का स्टॉक बेहद सीमित हो गया है, जिससे होटल संचालकों को उनकी दैनिक जरूरत के मुताबिक ईंधन नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में शादी-ब्याह और बड़े आयोजनों का सीजन होने के कारण गैस की मांग चरम पर है, लेकिन आपूर्ति बाधित होने से कैटरर्स और टेंट संचालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उत्तराखंड जैसे पर्यटन प्रधान राज्य के लिए यह स्थिति और भी घातक सिद्ध (शेष पृष्ठ 7पर)

गुंजन सुखीजा की पहल के बाद पौध जोतने की कार्यवाही पर लगेगी रोक

गदरपुर। क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को देखते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने प्रशासन द्वारा धान की तैयार नर्सरी (पौध) जोतने की कार्यवाही पर कड़ा संज्ञान लिया है। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर से फोन पर वार्ता की तथा गदरपुर में उपजिलाधिकारी व स्थानीय किसानों के साथ बैठक कर समाधान निकाला। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रशासन द्वारा किसानों की तैयार पौध को जोतने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाएगी। जिन किसानों ने

अपनी पौध तैयार कर ली है, उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए पौध बेचने की अनुमति दी जाएगी। किसान अपनी पौध केवल उन क्षेत्रों के किसानों को बेच सकेंगे जो निचले क्षेत्र में आते हैं अथवा उत्तर प्रदेश के किसानों को बेच सकेंगे। बैठक के दौरान गुंजन सुखीजा ने उपजिलाधिकारी से कहा कि प्रशासन द्वारा पौध जोतने की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और जिन किसानों ने पौध तैयार की है, उन्हें निचले क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश के (शेष पृष्ठ सात पर)

गैस सिलेण्डर जब्त करने पर हंगामा

रूद्रपुर। छापामारी के दौरान सिलेंडर पकड़े जाने के बाद गैस उपभेक्ताओं ने भारत गैस एजेंसी के समक्ष जमकर हंगामा कर पूर्ति अधिकारी को खरी खोटी सुनाई। घरेलू गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुपालन में आज पूर्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अनेक स्थानों पर छापामारी

की। इस दौरान अवैध रूप से रखे गये दो कामर्शियल सिलेंडर सहित कई घरेलू सिलेंडर बरामद किये गये वहीं दो गैस रिफ्लिंग किट भी बरामद की गई। जब सिलेंडरों से भरा उक्त वाहन भारत गैस एजेन्सी पहुंचा तो वहां पूर्ति अधिकारी की उपभोक्ताओं से तीखी नोंकझोंक हो गई। हंगामा कर रहे उपभोक्ताओं का आरोप था कि वह सिलेंडरों की कोई कालाबारी नहीं करते हैं बावजूद इसके उनके घरों से जबरन सिलेंडर उठा लिए गये। उनके पास सिलेंडरों के सही कागजात भी मौजूद हैं जिन्हें दिखाने पर भी अधिकारी उनकी कोई बात मानने को राजी नहीं है। वहीं पूर्ति अधिकारी का कहना था कि सिलेंडरों की कालाबाजारी व अवैध रिफ्लिंग की शिकायत पर अनेक स्थानों पर छापामारी की गई। जिसमें लगभग आठ सिलेंडर व दो रिफ्लिंग किट बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि (शेष पृष्ठ सात पर)

अग्निवीरों के भविष्य की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी: धामी

मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण में अग्निवीर सैनिकों के रूप में भर्ती होने वाले कैडेट्स के साथ संवाद किया

देहरादून । मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को भराड़ीसैंण में अग्निवीर सैनिकों के रूप में भर्ती होने वाले कैडेट्स के साथ संवाद किया। संवाद के दौरान कैडेट्स ने मुख्यमंत्री से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका मुख्यमंत्री ने सहजता से उत्तर दिया। संवाद के दौरान शंकर सिंह राणा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि सैनिक पुत्र होने के कारण आपने सैनिकों के जीवन और गतिविधियों को नजदीक से देखा है, क्या आपका मन सेना में जाने का नहीं हुआ? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में जाना अन्य सेवाओं की अपेक्षा अत्यंत सम्माननीय माना जाता है। उन्होंने कहा कि वे अपने जीवन को भी एक सैनिक के जीवन की तरह अनुशासित और समर्पित मानकर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने पिताजी के साथ रहते हुए उन्होंने सेना के अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा को करीब से देखा है। जिस प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ हमारे सैनिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उसी भावना से वे प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता की सेवा करने का प्रयास करते हैं। हिमांशु रौतेला ने प्रश्न किया कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते आप अपने परिवार को कैसे समय दे पाते हैं? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय होता है तो उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में प्रदेश के सभी लोग उनका परिवार हैं और सभी गांव उनके अपने गांव हैं। ओ. पी. कण्डारी ने पूछा कि जब हम अग्निवीर के रूप में अपनी सेवा पूरी कर वापस आएंगे, उसके बाद सरकार हमारे रोजगार के लिए क्या व्यवस्था कर रही है? मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्दीधारी पदों पर अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा भी अनेक क्षेत्रों में अग्निवीरों को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर अग्निवीर के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना

सरकार की जिम्मेदारी है। रितेश पंवार ने मुख्यमंत्री से पूछा कि आपकी पहचान "धाकड़ धामी" के रूप में क्यों बनी? मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार जनता के साथ सदैव सौम्य होना चाहिए। हालांकि राज्यहित और जनहित में कई बार कठोर और साहसिक निर्णय लेने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है तथा दंगा रोधी कानून भी लागू किया गया है। पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार ने जन अपेक्षाओं और प्रदेशहित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अमन सेमवाल ने पूछा कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान का क्या राज है? मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कार्य करने की ऊर्जा और प्रेरणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार जन अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और आज अनेक क्षेत्रों में उत्तराखण्ड देश में अग्रणी स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनभावनाओं के अनुरूप राज्य के विकास को नई गति देने के लिए पूरे संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस अवसर पर अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक सीमांत और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं। देवभूमि उत्तराखण्ड की विशेषता है कि यहां लगभग हर परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना या अर्द्धसैन्य बलों में सेवाएं दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना तेजी से आत्मनिर्भर बन रही है। रक्षा क्षेत्र में भारत का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है और भारतीय सेना वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और सक्षम सेना के रूप में स्थापित हुई है। सेना में निरंतर आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। देहरादून में भव्य सैन्यधाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें राज्य के वीर बलिदानियों की गौरवगाथाएं और स्मृतियां संजोई जाएंगी। उन्होंने कहा कि वे पूर्व सैनिकों को अपने अभिभावक के रूप में देखते हैं। इस अवसर पर यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोठियाल (सेनि.), पूर्व सैनिकगण तथा अग्निवीर उपस्थित थे।

उत्तराखंड को शहरी नियोजन और सुधारों के लिए मिले 264.50 करोड़

देहरादून (उद संवाददाता)। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य को शहरी भूमि एवं नियोजन सुधारों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत भाग-दस ए के तहत उत्तराखंड को 264.50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता ऋण स्वीकृत की गई है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अनुशंसा के आधार पर यह राशि राज्य सरकार को प्रदान की गई है। उत्तराखंड सरकार ने इस प्रोत्साहन राशि के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे स्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने राज्य को यह सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है। यह राशि राज्य में प्रस्तावित विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई है, जिससे शहरी विकास, भूमि प्रबंधन और नियोजन सुधारों को गति मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा यह पूरी राशि एकमुश्त किस्त में राज्य को जारी कर दी गई है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास को निरंतर प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड में योजनाबद्ध शहरी विकास, आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रणाली और मजबूत आधारभूत ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में बेहतर नियोजन, सुव्यवस्थित विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस सहायता से प्रदेश के शहरों में संतुलित और टिकाऊ विकास को गति मिलेगी तथा आम नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

फसलों को भालुओं से होने वाले नुकसान पर भी मुआवजा देने की तैयारी में जुटी सरकार

देहरादून (उद संवाददाता)। वन्य जीवों से होने वाले विभिन्न प्रकार के नुकसान पर अब तक मुआवजे की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, लेकिन धामी सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर जनता को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार के प्रयास यहीं नहीं थमे हैं और अब भालुओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को भी मुआवजे के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि भालुओं द्वारा मकानों और भवनों को पहुँचाई जाने वाली क्षति पर सरकार पहले ही मुआवजे की व्यवस्था सुनिश्चित कर चुकी है।धामी सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान वन्य जीवों के हमलों से होने वाली जनहानि और अन्य नुकसानों पर विशेष गंभीरता दिखाई है। वन्य जीवों के हमले में मृत्यु होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि को चार लाख से बढ़ाकर छह लाख रुपये करना सरकार का एक संवेदनशील फैसला रहा है। इसके साथ ही अब ततैंया और मधुमक्खी के हमले में होने वाले नुकसान पर भी मुआवजे का प्रावधान किया गया है।विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सदन को अवगत कराया कि भालुओं के व्यवहार में आए बदलाव और उससे होने वाली क्षति पर सरकार निरंतर नजर रख रही है। इसी क्रम में भारतीय वन्य जीव संस्थान को इस पूरे विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सुबोध उनियाल ने बताया कि इस तकनीकी रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भालुओं द्वारा फसलों को पहुँचाए जा रहे नुकसान के बदले किसानों को मुआवजा देने के प्रस्ताव पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ विचार कर रही है।

भाजपा की बैठक में बनी आगामी रणनीति, हल्द्वानी में होगी भव्य रैली

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊँ संभाग कार्यालय में बुधवार को प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन की मजबूती और वर्तमान में चल रहे विभिन्न अभियानों की समीक्षा के साथ-साथ भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से मंथन किया गया। इस दौरान विशेष रूप से चल रहे एसआईआर अभियान के संबंध में कार्यकर्ताओं को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई और इसे जन-जन तक पहुँचाने का आह्वान किया गया।बैठक के केंद्र में आगामी 21 या 22 मार्च को हल्द्वानी में प्रस्तावित भव्य रैली की तैयारियां रहीं। अजेय कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श करते हुए कहा कि यह रैली संगठन की शक्ति का प्रदर्शन होगी, जिसके लिए अभी से धरातल पर जुटकर तैयारी करना आवश्यक है। उन्होंने आगामी संगठनात्मक अभियानों की सफलता के लिए प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता को सक्रिय भूमिका निभाने और जनसंपर्क तेज करने के निर्देश दिए।इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नैनीताल प्रताप सिंह बिष्ट, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बलबीर धुनियाल, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह नेगी और पिथौरागढ़ जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने भी अपने विचार साझा किए। बैठक में जिला महामंत्री रंजन सिंह बर्गली, विनीत अग्रवाल सहित कई दर्जा राज्य मंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने एक स्वर में आगामी कार्यक्रमों को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया।

फायर वाचर्स को मिला दस लाख का सामूहिक बीमा और ग्राम पंचायतों को मिली प्रोत्साहन राशि

देहरादून । प्रदेश में वनाग्नि को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिन गंभीर प्रयासों को शुरू किया गया है, उनसे सार्थक परिणामों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। सरकार ने वन विभाग के माध्यम से एक वर्ष के भीतर ग्रामीणों से पांच करोड़ 42 लाख रुपये का पिरूल खरीदा है। चीड़ के जंगलों में आग लगने के मूल कारण को खत्म करने के लिए ग्रामीणों से वर्ष 2025 में 5532 टन पिरूल खरीदा गया है। इस लक्ष्य को अब बढ़ाकर 8555 टन कर दिया गया है। सरकार की मंशा है कि पिरूल एकत्रित कर आग की आशंका को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा दिया जाए।वनाग्नि को रोकने के लिए धामी सरकार के प्रयासों में जन जागरूकता पर भी फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1239 जागरूकता कैंप लगाए गए हैं। सबसे अहम काम सरकार ने यह किया है कि ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी गठित की है, जो विभाग के साथ मिलकर जंगल बचाने में जुट रही हैं। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत को 30 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। मंगलवार को बजट सत्र प्रश्नकाल में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने यह जानकारी साझा की।वनाग्नि के दौरान फायर वाचर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए धामी सरकार ने पहली बार बीमे का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया है। फायर वाचर्स का दस लाख का सामूहिक बीमा किया गया है। 5600 फायर वाचर्स ने पिछले वर्ष वनाग्नि रोकने में अपना योगदान दिया था।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा० उच्चतम न्यायालय में योजित एस०एल०पी० 31060-31061/2025 में पारित आदेश दि०27.01.2026 के अनुपालन में याचिकाकर्ता द्वारा बोया हुआ गन्ना अवशेष जो खेतो में खड़ा है की **खुली नीलामी 16-03-2026 को राजस्व ग्राम गंगोली में प्रातः 11:00 बजे सुबह से नियोजित होगी ।** इच्छुक बोलीदाता नियत तिथि व समय पर **प्राग फार्म गोकुल नगर तहसील किच्छा उपस्थित हो प्रति भाग ले सकते हैं।**

न्यूनतम बोली 300-/ रू० प्रति कु० होगी ।

प्रॉप्रिटर
मनोज नरायन अग्रवाल
प्राग फार्म गोकुल नगर
8057911622

सांसद अजय भट्ट ने लोकसभा में उठाया ग्रामीण पर्यटन का मुद्दा

जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे विकास के लिए पांच लाख तक की सहायता देगी सरकार

रूद्रपुर। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने लोकसभा सत्र के दौरान ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के

लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से अतारांकिक प्रश्न में पूछा की सरकार देश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना बना रही है इसके अलावा ग्रामीण पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन की क्षमता का दोहन करने के लिए राज्य संघ और क्षेत्रवार कौन-कौन सी योजनाएं प्रस्तावित हैं और देश में ग्रामीण पर्यटन की क्या स्थिति है इसके अलावा उन्होंने पूछा कि उत्तराखंड सहित राज्यों का क्या ब्यौरा है इसके लिए सरकार कितनी धनराशि आवंटित कर रही है। सदन में सांसद अजय भट्ट के आतंरिकिक सवाल पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जवाब दिया कि पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन, राष्ट्रीय तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान मिशन (प्रशाद) और पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता नामक योजनाओं के तहत, पिछडे ग्रामीण क्षेत्रों/जनजातीय क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत ग्रामीण परिपथ को विषयगत परिपर्थों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया। स्वदेश दर्शन योजना के ग्रामीण परिपथ के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। स्वदेश दर्शन योजना को गंतव्य-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी एवं जिम्मेदारीयुक्त स्थलों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के नाम से नया रूप दिया गया। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने एवं पर्यटन स्थलों को स्थायी और जिम्मेदारीयुक्त स्थलों के रूप में परिवर्तित करने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की एक उप योजना के रूप में चुनौती आधारित गंतव्य विकास के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन के संवर्धन के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएम-जेयूजीए) के तहत जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे का विकास (स्वदेश दर्शन योजना की एक उप-योजना) के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्ताव तैयार करने के लिए टॅम्प्लेट सहित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने और जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे का विकास करना है। यह दिशानिर्देश होमस्टे मालिकों के तकनीकी कौशल और प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। उक्त पहल में ग्राम समुदाय की आवश्यकता के लिए 5 लाख रुपये तक, प्रत्येक घर के लिए दो नए कमरों के निर्माण हेतु 5 लाख रुपये तक और मौजूदा कमरों के नवीनीकरण के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता सहित 1000 होमस्टे का विकास करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा में, सरकार ने होमस्टे के लिए पीएमएमवाई (मुद्रा) ऋण योजना में एक अलग श्रेणी शुरू की। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होमस्टे भी इस ऋण का लाभ उठाने के पात्र हैं। संवर्धनात्मक अभियान के भाग के रूप में, राज्य सरकारों और हितधारकों के लिए दिनांक 11.09.2025 को नई दिल्ली में होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से होमस्टे इकाइयों के लिए मुद्रा ऋण का लाभ उठाने हेतु हितधारकों के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका के रूप में वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के सहयोग से 27 सितंबर, 2025 को होमस्टे हेतु मुद्रा ऋण के लिए गाइड पर एक पुस्तिका भी लॉन्च की गई। पर्यटन मंत्रालय ने 27 सितंबर, 2024 को पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक एक राष्ट्रीय उत्तरदायी पर्यटन पहल शुरू की, जिसके माध्यम से महिलाओं और युवाओं के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि वे होमस्टे मालिकों, विभिन्न पाक-कला एवं व्यंजन संबंधी अनुभव प्रदाताओं, सांस्कृतिक गाइड, प्राकृतिक गाइड, साहसिक गाइड, और अन्य भूमिकाओं के रुप में, गंतव्य की क्षमता के आधार पर लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए इन कौशलों का लाभ उठा सकें। पर्यटन मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप भी तैयार किया है जिसे सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित किया गया।

आकांक्षा ऑटोमोबाइल शोरूम में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, शातिर चोर गिरफ्तार

काशीपुर (उद संवाददाता)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में आईटीआई पुलिस ने आकांक्षा ऑटोमोबाइल शोरूम में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से शोरूम से चोरी किया गया भारी मात्रा में स्पेयर पार्ट्स और अन्य सामान बरामद हुआ है। गौरतलब है कि 10 फरवरी 2026 को बाजपुर निवासी तजिंदर सिंह पुत्र रंजीत सिंह ने तहरीर देकर बताया था कि 8 फरवरी की रात अज्ञात चोरों ने उनके बाजपुर रोड स्थित आकांक्षा ऑटोमोबाइल शोरूम में घुसकर स्पेयर पार्ट्स चोरी कर लिए थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया था।प्रभारी निरीक्षक कोतवाली आईटीआई के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम सोमवार की रात्रि क्षेत्र में गश्त

और शांति व्यवस्था के लिए निजी वाहन से तैनात थी। इसी दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर परमानंदपुर हाईवे के नीचे से संदिग्ध अभियुक्त इकराम उर्फ गुड्डू पुत्र राज खां निवासी बिधोलिया थाना सीबीगंज जनपद बरेली उत्तर प्रदेश को दबोच लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से चोरी किया गया माल बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में बढ़ोत्तरी कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया है।पकड़े गए अभियुक्त इकराम उर्फ गुड्डू के पास से पुलिस ने मारुति सुजुकी के ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एयर क्लीनर, ईसीएम और अन्य कीमती स्पेयर पार्ट्स के पैकेट बरामद किए हैं। इसके अलावा एक थैला, मफलर और टोपी भी बरामद हुई है। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक शंकर सिंह बिष्ट, हेड कांस्टेबल सिराज हुसैन, दीपक, कांस्टेबल बलवंत सिंह और धर्मेंद्र भारती शामिल रहे।

अपराधियों पर प्रहार, गैंगस्टर एक्ट में चार गिरफ्तार

काशीपुर (उद संवाददाता)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर अजय गणपति के निर्देशों के क्रम में जनपद में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध सख्त अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक काशीपुर और क्षेत्राधिकारी काशीपुर व बाजपुर के पर्यवेक्षण में आईटीआई थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत लोक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले एक संगठित गिरोह के चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध थाना आईटीआई में धारा 2/3 गिरोहबंद अधि नियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। यह गिरोह क्षेत्र में आम जनता के साथ मारपीट करने, डराने-धमकाने और जमीनों की फर्जी बिक्री दिखाकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था। समाज में इनके भय और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने यह कठोर कदम उठाया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में आशीष चौहान उर्फ

पटवारी, अमरजीत सिंह, गुरुप्रेम सिंह और कुलविंदर सिंह उर्फ जस्सी शामिल हैं। पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूरी करने के बाद सभी को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। एसएसपी अजय गणपति ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अपराधियों और संगठित गिरोहों के विरुद्ध यह अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही को अंजाम देने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार, राजेंद्र सिंह डांगी, सुनील सुतेड़ी, जावेद मलिक, देवेन्द्र मेहता, कौशल भाकुनी, सौरभ भारती, देवेन्द्र सामन्त, विनय कुमार, दीपक, हरीश, गिरीश मठपाल और नरेश चौहान शामिल रहे।

घरेलू गैस की कमी नहीं, इंडेन का भंडारण फुल

सितारगंज ।पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण उपभोक्ताओं में घरेलू गैस प्रभावित होने का भ्रम फैला हुआ हैं। इंडेन गैस एजेंसी के मैनेजर ने स्पष्ट किया है कि गैस आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। भंडारण फूल है। इसके बाद गैस उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण दुनिया भर में गैस एलपीजी, तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। इस कारण क्षेत्र के उपभोक्ताओं में घरेलू गैस को लेकर किल्लत का भ्रम फैल गया था। जबकि क्षेत्र में सप्लाई होने वाली गैस की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में है। इंडेन गैस एजेंसी के मैनेजर राजेंद्र सिंह गड़िया ने बताया कि क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए उनके पास गैस का भंडारण पर्याप्त है। गैस आपूर्ति वितरण में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि बुधवार को गैस बुकिंग प्रभावित हुई है जो जल्द ही दुरुस्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सितारगंज क्षेत्र में घरेलू गैस के 32000 उपभोक्ता हैं। गैस की किल्लत न बने इसके लिए उन्होंने पूर्व में ही भंडारण कर रखा है।

बिना अनुमति लगाई गई ग्रीष्मकालीन धान की पौध नष्ट

गदरपुर। जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशों के क्रम में तहसील गदरपुर क्षेत्र में बिना अनुमति लगाई गई ग्रीष्मकालीन धान की पौध पर प्रशासन ने कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार ग्राम चंदन नगर के खसरा संख्या 426 में लगभग 0.085 हेक्टेयर तथा ग्राम बरीराई के खसरा संख्या 0035 में लगभग 0.202 हेक्टेयर भूमि पर बिना अनुमति के लगाई गई ग्रीष्मकालीन धान की पौध को राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नष्ट कराया गया।कार्रवाई के दौरान कुछ कृषकों द्वारा विरोध भी किया गया, जिस पर मौके पर ही उन्हें समझाया गया कि ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई के लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक है। साथ ही यह भी बताया गया कि यदि खेत में अन्य किसी फसल का विकल्प उपलब्ध नहीं है तो अनुमति प्राप्त कर ही ग्रीष्मकालीन धान का रोपण किया जा सकता है। अधिकारियों ने किसानों को अन्य फसलों से होने वाले लाभ तथा ग्रीष्मकालीन धान की खेती से भूजल स्तर में गिरावट के कारण प्रकृति और मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की भी जानकारी दी।इस कार्रवाई के दौरान राजस्व निरीक्षक विनोद कुमार, भगत सिंह, राजस्व उप निरीक्षक सरताज अली, नरेंद्र कुमार, हेमा मिश्रा सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।प्रशासन ने सभी कृषकों से अपील की है कि वे बिना अनुमति के धान की पौध न लगाएं तथा जल संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें।

ससुरालियों ने मां बेटे से मारपीट कर किया अधमरा

इंसाफ के लिए सीएम पोर्टल पर लगाई गुहार, आईटीआई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल

काशीपुर। आईटीआई पुलिस से यदि इंसाफ की अपेक्षा रखना है तो इसके लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति से पुलिस पर दबाव बनाना होगा या फिर सीएम की चौखट पर न्याय की गुहार लगाना होगा। ताजे प्रकरण में खड़कपुर देवीपुरा निवासी एक युवक व उसकी मां को विवादों के चलते घर धमके ससुरालियों ने मारपीट कर अधमरा कर दिया। इंसाफ के लिए पीड़ित पक्ष को सीएम पोर्टल का सहारा लेना पड़ा। खड़कपुर देवीपुरा थाना आईटीआई निवासी एक युवक ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेज कर बताया कि वर्ष 2024 की 23 अप्रैल को उसका शादी ढाकवाला मजरा, सहसपुरी, तहसील ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश निवासी हुकुम पाल की पुत्री अंशु चौहान से हुई। आरोप है कि शादी के कुछ दिन ठीक-ठाक बीते इसके बाद नव विवाहिता तथा उसके परिवार वालों ने वर पक्ष को परेशान करना शुरू कर दिया। हालिया घटनाक्रम के बारे में शिकायतकर्ता ने बताया कि बीते 7 जनवरी की दोपहर लगभग 12:30 बजे उसके घर पर उसकी पत्नी के पिता हुकुम सिंह, मुकेश चौहान, अमन चौहान, राखी चौहान, राजबाला, अंकित चौहान व अन्य रिश्तेदार हथियारों से लैस होकर चार गाड़ियों भरकर घर आ धमके और जबरदस्ती घर में घुस आये। इन लोगों ने आते ही उसे अकेला देखकर उसके साथ लात-घूंसों व बैल्टों से मारपीट व गाली-गलौज शुरू कर दी। उसकी माता बीच-बचाव करने आयी तो उक्त लोगों ने उसकी माता के साथ भी बदसलूकी की और हाथापाई की। युवक ने बताया कि उसकी माता के हाथों पर उसे बचाते हुए बैल्टें लगीं, जिससे उसकी माता के हाथ पर चोट आयी है। उसके भी सिर पर गले पर खुली चोट आयी है व अन्य जगह शरीर पर गुम चोटें आयी हैं। उसने सहायता के लिए पुलिस को कॉल करनी चाही तो अंकित चौहान व उक्त सभी ने साथ मिलकर उसका मोबाइल उससे छीन लिया और अपने साथ ले गये तथा जाते जाते इन लोगों ने उन्हें भविष्य में देख लेने व जान से मारने की धमकी दी है। मारपीट के इस मामले में इंसाफ के लिए पीड़ित पक्ष को मुख्यमंत्री से गुहार लगाना पड़ा। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईटीआई पुलिस मित्रता सेवा सुरक्षा के नाम पर किस हद तक संवेदनशील है। फिलहाल मुख्यमंत्री के आदेश पर आईटीआई कोतवाली पुलिस ने उक्त 6 नामजद व अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 191(2), 332(सी), 351(2), 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

अवैध खनन भरे वाहनों से होती है वसूली

सरकार व शासन के सख्त निर्देश के बावजूद आईटीआई थाना क्षेत्र में खनन माफिया कोशी का सीना चाक कर बड़े पैमाने पर अवैध खनन को राज्य की सीमा पार कर यूपी के स्टोन क्रशरों में खपत कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि थाना क्षेत्र के आधा दर्जन स्थानों पर पुलिस की शह पर खनन भरे वाहनों से अवैध उगाही की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि थाना क्षेत्र में मुस्तैदी के नाम पर पुलिस ओवरलोड एवं ओवर हाइट वाहनों से अवैध वसूली एवं जरायम कारोबारियों एवं अपराधी तत्वों को संरक्षण देने का काम कर रही है।

नव विवाहिता के दांपत्य जीवन में पड़ोसी युवक खोल रहा जहर

काशीपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति जहां एक ओर महिलाओं के संग होने वाले अपराध को लेकर गंभीर हैं वहीं आईटीआई थाना पुलिस एसएसपी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए फरियादियों को थाने से दुत्कार कर भगाने अथवा उल्टे कानून के चुंगल में फसाने का भय दिखा रही है। पुलिस की इस कार्यशैली से क्षेत्रीय जनता में असंतोष है। ताजे घटनाक्रम के बारे में पैगा चौकी क्षेत्र निवासी एक महिला ने बीते 6 मार्च को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक उसकी पुत्री को पिछले काफी समय से परेशान कर रहा है। महिला ने पुलिस को बताया कि बीते 19 फरवरी को उसके पुत्री की शादी थी। पड़ोसी युवक ने शादी में व्यवधान डालने का प्रयास किया। उसने धमकी दी कि यदि लड़की की शादी की तो परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। परिजनों की कड़ी सुरक्षा में शादी किसी तरह संपन्न हो गई लेकिन इसके बाद आरोपी युवक ने नव विवाहिता तथा उसके पति के मोबाइल पर अश्लील एवं धमकी भरे मैसेज भेजना शुरू कर दिए। आरोपी के इस कृत्य से नव विवाहिता का दांपत्य जीवन दिन-ब-दिन खराब होता जा रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि थाने चौकी के लगातार चक्कर काटने के बावजूद उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। पता चला है कि जिस लड़की का यह मामला है उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है। पुलिस को जब इसका पता चला तो उसने पीड़ित पक्ष को यह कहकर डराना शुरू कर दिया कि मुंह खोला तो नाबालिग की शादी करने के आरोप में सबको जेल जाना पड़ेगा। पुलिस के इस रवैए से पीड़ित परिवार सदमे में है।

उत्तराखंड विधानसभा में देवभूमि परिवार विधेयक पेश, आईडी में वरिष्ठ महिला सदस्य होगी मुखिया

देहरादून (उद संवाददाता)। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मंगलवार को देवभूमि परिवार विधेयक 2026 को सदन पटल पर रख दिया है। इस विधेयक के कानून बन जाने पर प्रदेश में एकीकृत और सत्यापित परिवार आधारित डेटाबेस देवभूमि परिवार की स्थापना हो सकेगी। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न विभागों में बिखरे लाभार्थी डेटा को एक मंच पर लाकर योजनाओं के संचालन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समन्वित बनाना है। देवभूमि परिवार आईडी में मुखिया के तौर पर परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठतम महिला सदस्य का नाम दर्ज होगा। वर्तमान में राज्य के अलग अलग विभाग अपनी अपनी योजनाओं के लिए अलग लाभार्थी डेटाबेस का उपयोग करते हैं। इसके कारण कई बार लाभार्थी आंकड़ों का दोहराव, पुनः सत्यापन की जटिल प्रक्रियाएँ और विभागों के बीच समन्वय की कमी जैसी समस्याएँ सामने आती हैं। इससे न केवल प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ता है, बल्कि योजनाओं के आकलन और प्रभावी क्रियान्वयन में भी बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। अब इस विधेयक के माध्यम से राज्य में एक एकीकृत परिवार स्तरीय डेटा भंडार स्थापित किया जाएगा, जो

विभिन्न विभागों और एजेंसियों के लिए लाभार्थी संबंधी सूचनाओं का एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करेगा। इससे योजनाओं का बेहतर लक्ष्योन्मुखी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सहायता अधिक प्रभावी ढंग से पहुँच सकेगी।इसके साथ ही, इस डेटा प्रणाली के प्रभावी प्रबंधन, संरक्षण और संरचनात्मक सुधारों के लिए एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र का भी गठन किया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत विभागों के बीच सुरक्षित और विनियमित डेटा आदान प्रदान की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी, जिससे योजनाओं के बेहतर लक्षित वितरण और समन्वय को मजबूती मिलेगी। यह पूरी व्यवस्था डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जाएगी, ताकि नागरिकों के डेटा का उपयोग सहमति, पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि परिवार विधेयक 2026 सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और उत्तराखंड के नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुँच सकेगा। सदन में इस विधेयक के साथ ही उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2026, उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (संशोधन) विधेयक 2026, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक 2026, उत्तराखंड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम 2026, उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2026, उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक 2026, उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक 2026, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 2026 और उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक 2026 भी प्रस्तुत किए गए।

धामी सरकार के चार साल में 819 पंचायत भवनों का हुआ कायाकल्प

सात हजार किमी सड़कें हुई गड्ढा मुक्त

देहरादून (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के बीते चार साल में प्रदेश में 819 पंचायत भवनों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया गया है। प्रदेश में पंचायत भवनों की कुल संख्या 5867 है जिनमें से 1134 पंचायत भवन लंबे समय से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में चल रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायतीराज विभाग को अभियान चलाकर इन भवनों का पुनर्निर्माण करने के निर्देश दिए थे जिसके बाद बीते चार वर्षों में विभाग ने 819 भवनों का कार्य पूर्ण कर लिया है और शेष भवनों पर कार्य जारी है। मंगलवार को विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन को यह जानकारी दी।प्रदेश में लोकनिर्माण विभाग द्वारा नवंबर के प्रथम सप्ताह तक सात हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। सदन में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के क्रम में विभाग ने वर्ष 2025-26 में मानसून काल से पूर्व 3134 किमी लंबी सड़कों को सुधारा जबकि मानसून के बाद 10 नवंबर 2025 तक 4149.17 किमी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया। इस अभियान के दौरान अकेले हरिद्वार जनपद में 313 किमी से अधिक लंबी सड़कों की स्थिति सुधारी गई।इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न तीर्थ स्थलों को रोपवे से जोड़ने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। पर्यटन मंत्री ने विधानसभा में बताया कि विभाग ने कद्दूखाल से सुरकंडा देवी मंदिर के लिए निजी सार्वजनिक भागीदारी मोड में रोपवे का संचालन शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त जनपद चम्पावत में ठुलीगाड़ से पूर्णागिरी रोपवे का निर्माण कार्य जारी है। वहीं जनपद उत्तरकाशी में जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक के लिए रोपवे विकसित किया जा रहा है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है।

उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने जीते कई पदक

रुद्रपुर(उद संवाददाता)। हैदराबाद के रंगा रेड्डी में 6 से 10 मार्च 2026 तक आयोजित 7वीं नेशनल पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देवभूमि का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने स्वर्ण सहित कई पदक अपने नाम किए, जिससे खेल प्रेमियों और परिजनों में भारी उत्साह है। उत्तराखंड के स्टार खिलाड़ी चिराग बरेठा ने कोर्ट पर अपनी बादशाहत कायम रखते हुए पुरुष युगल (मेंस डबल्स) स्पर्धा में पंजाब के राज कुमार के साथ जोड़ी बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अतिरिक्त, चिराग ने पुरुष एकल (मेंस सिंगल्स) में कांस्य और मिक्स्ड डबल्स में झारखंड की संजना कुमारी के साथ मिलकर कांस्य पदक जीतकर पदकों की हैट्रिक लगाई। वहीं, होनहार खिलाड़ी हर्षित राजपूत ने भी शानदार खेल दिखाते हुए भ्6 कैटेगरी के मेंस डबल्स मुकाबले में कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में उत्तराखंड की बेटियों ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शिवांगी पांडेय ने महिला एकल स्पर्धा में विपक्षी खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया। इसके साथ ही प्रेमा विश्वास ने भी सिंगल्स और डबल्स दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक हासिल कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उत्तराखंड पैरा बैडमिंटन के संयोजक हरीश चौधरी ने खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इनकी मेहनत और लगन ने साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। खिलाड़ियों की इस बड़ी उपलब्धि पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनोज सरकार, पैरालंपिक एसोसिएशन की सचिव अमिता, एनआईओएस कोच प्रेम कुमार, भारत भूषण चुघ, पूर्व मेयर रामपाल सिंह, अनिल चौहान, जे.बी. सिंह, डॉ. नागेंद्र प्रसाद शर्मा, सुभाष अरोड़ा, पार्षद शालू पाल, सुशील चौहान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने बधाई दी है।

पूर्व उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन के लिए मिले 289.98 करोड़

देहरादून (उद संवाददाता)। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में पूर्व उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट में इस मद के लिए 289 करोड़ 98 लाख 29 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपनल कर्मियों ने विभिन्न विभागों में लंबे समय तक महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था को लागू करने हेतु बजट में पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय सरकार की समावेशी और संवेदनशील शासन व्यवस्था का प्रतीक है। सरकार लगातार कर्मचारियों के कल्याण, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रदेश में पारदर्शी व उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से पूर्व उपनल कर्मियों को राहत मिलेगी

53वीं मां वैष्णो दरबार यात्रा के लिए कल रवाना होंगे श्रद्धालु

रुद्रपुर। श्री सनातन धर्म सभा द्वारा आयोजित 53वीं मां वैष्णो दरबार यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था कल प्रातः 7 बजे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर (पांच मंदिर) से बस द्वारा रवाना होगा। सभा के अध्यक्ष एडवोकेट महेश बब्बर ने बताया कि यह

धार्मिक यात्रा रुद्रपुर से प्रारंभ होकर श्रद्धालुओं को विभिन्न पवित्र शक्तिपीठों के दर्शन कराएगी।उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालु चंडीगढ़, पंचकुला, नैना देवी और पठानकोट होते हुए मां वैष्णो दरबार के दर्शन करेंगे। इसके पश्चात श्रद्धालु चामुंडा देवी, कांगड़ा देवी, बगलामुखी, चिंतपूर्णी और ज्वाला जी के दर्शन भी करेंगे।एडवोकेट महेश बब्बर ने बताया कि श्रद्धालु मां ज्वाला जी से ज्योत लेकर 18 मार्च 2026 को रुद्रपुर वापस पहुंचेंगे। इस अवसर पर ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत करते हुए ज्योत को श्री लक्ष्मी नारायण (पांच मंदिर) में विधिवत स्थापित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि यात्रा का आने-जाने का किराया 6000 रुपये प्रति सीट निर्धारित किया गया है, जबकि श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था श्री सनातन धर्म सभा द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी और सीट बुकिंग के लिए इच्छुक श्रद्धालु श्री सनातन धर्म लक्ष्मी नारायण मंदिर, रुद्रपुर (जनपद ऊधम सिंह नगर) में संपर्क कर सकते हैं।

SAHAS Homeo
साहस होम्यो मेडिकल स्टोर एवं क्लीनिक
जर्मन तथा सभी प्रकार के होम्योपैथिक व बायोकैमिक दवाईयों के विक्रेता

डॉ. यश पाण्डेय
होम्योपैथिक फिजिशियन
बी.एच.एम.एस., जयपुर
चर्म रोग | गुर्दा रोग | पेट रोग
गुदा रोग | लिवर सम्बन्धि रोग
अन्य रोग • स्पान्डीलाईटिस • श्वास रोग • मोटापा • दमा • प्रोस्टेट • माइग्रेन • टान्सिल • एलर्जी • ब्रोनकाइटिस
बच्चों के रोग • पेट का दर्द • अपच • कान में संक्रमण / दर्द • खांसी • जुकाम • निमोनिया • बुखार • दांत निकलना
साहस होम्यो क्लीनिक
निकट गुरुद्वारा, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी
मो. 9456727473, 9410514531 रविवार अवकाश

ई-केवाईसी व डीएसी के बिना नहीं मिलेगी गैस, 25 दिन बाद ही होगी अगली बुकिंग

गदरपुर। गदरपुर गैस सर्विस के प्रबंधक गणेश आर्य ने सभी उपभोक्ताओं को सूचित किया है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग अब डिलीवरी के 25 दिन बाद ही की जा सकेगी। इसके साथ ही बिना डीएसी , ई-केवाईसी और गैस किताब के किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। एजेंसी प्रबंधन ने बताया कि क्षेत्र में गैस की कोई कमी नहीं है और सभी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस वितरण किया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपने गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करवा लें और गैस बुकिंग कराने के बाद अपनी गैस किताब में दिनांक व डीएसी दर्ज कराकर ही गैस लेने आएं।प्रबंधक ने जानकारी दी कि 7 मार्च 2026 से गैस सिलेंडर के दाम बढ़कर 933 रुपये हो गए हैं, जो बुकिंग के समय लागू होंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि डिलीवरी के 25 दिन पूरे होने के बाद ही अगली गैस बुकिंग संभव होगी।एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं से नियमों का पालन करने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई है।

बढ़ती डग्गामारी व परिवहन संचालन की खिलाफ रोडवेज कर्मी हुए मुखर

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। शहर में बढ़ती डग्गामारी और अवैध परिवहन संचालन के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों ने मोर्चा खोलकर आगामी 26 मार्च तक समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, कुमाऊं क्षेत्र के तत्वावधान में मंगलवार को विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और संभागीय परिवहन अधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी के माध्यम से प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अवैध परिवहन गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की ।इस दौरान संयुक्त परिषद, रोडवेज कर्मचारी यूनियन, एम्पलाइज यूनियन, भारतीय मजदूर संघ और एससी-एसटी श्रमिक संगठन से जुड़े कर्मचारियों ने एकजुट होकर कहा कि हल्द्वानी बस अड्डे और आसपास के क्षेत्रों में अवैध बसों, टैक्सियों और प्राइवेट वाहनों का अनियंत्रित संचालन रोडवेज को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। कर्मचारी संगठनों ने प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं, जिनमें प्रमुख रूप से अवैध अंतरराज्यीय बसों पर रोक लगाने, नगर में ऑनलाइन संचालित हो रही कई अवैध अंतरराज्यीय बसें जो सड़क किनारे यात्रियों को बैठाकर संचालित हो रही हैं पर तत्काल रोक लगाने, टैक्सियों का संचालन केवल भोटिया पड़ाव टैक्सी स्टैंड से ही सुनिश्चित कर बस अड्डे के आसपास टैक्सियों के अवैध जमावड़े पर रोक लगाने, प्राइवेट वाहनों के अवैध संचालन पर कार्रवाई कर बस अड्डे के सामने सड़क पर खड़े होकर यात्रियों को बैठाने वाले प्राइवेट वाहनों के संचालन को पूरी तरह बंद करने की मांग भी उठाई, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रह सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी और एसपी सिटी ने संगठन के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि अवैध डग्गामारी और अनियमित परिवहन गतिविधियों के खिलाफ जल्द ही ठोस और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 26 मार्च तक उनकी मांगों पर धरातल पर कार्रवाई नहीं हुई, तो कुमाऊं क्षेत्र के सभी कर्मचारी संगठन संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के समक्ष उग्र धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस दौरान आन सिंह जीना, मुकेश वर्मा, कौशल जोशी, राजीव भट्ट, मोहन बोरा, रमेश कपिल, जीवन आर्य, महेश दफौटी, कमल पपने, शंकर सिंह, जगदीश कांडपाल, आनंद बिष्ट, नवनीत कपिल, पूरन राम, जगमोहन, ललित पांडे, मनिंदर सिंह, जीवन चंद, तारा जोशी, प्रमोद बरगली, मोहसिन, मनोज मनराल, कार्तिक, नवीन बिष्ट, योगेश जोशी, बलराम सागर, रौतेला, प्रकाश संभल, सुमित कुमार, हेमंत गढ़िया, संजय, संतोष, नवीन, रचना बिष्ट, हेम, गुणवंत, मोहित कुमार, आनंद बल्लभ, राहुल रावत सहित सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे।

भागवत कथा से पूर्व धूमधाम से निकली भव्य कलश यात्रा

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। आदर्श कॉलोनी स्थित वैष्णवी शक्तिपीठ आश्रम (प्राचीन श्री वैष्णो देवी मंदिर) से वैष्णवी शक्ति पीठाधीश्वरी ब्रह्मलीन मां हंसेश्वरी भारती महाराज की सत प्रेरणा में एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा पूज्यनीय स्वर्ग फार्म वाली वाली देवी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित भागवत कथा की पूर्व संध्या पर निकाली गई, जिसमें भक्तों का अटूट उत्साह देखने को मिला। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगकर क्षेत्र के लोगों में आनंद और उत्साह का संचार करना था। कलश यात्रा की शुरुआत से पहले विद्वान पंडितों ने भागवत जी का विधि विधान से पूजन किया और संकीर्तन के साथ संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया।ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्तिमय नारों के बीच यात्रा ने एक अद्भुत रूप धारण किया। एक सुंदर रथ पर विराजमान पूज्यनीय देवी का आकर्षक स्वरूप, भगवान कृष्ण की मनमोहक झांकी और दुर्गा माता की दिव्य झांकी यात्रा के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इस्कॉन मंदिर से आई भक्त मंडली ने भी अपनी विशेष उपस्थिति से शोभा यात्रा की गरिमा बढ़ाई। यात्रा के दौरान महिलाओं ने सिर पर कलश और हाथों में झंडे लेकर शोभा बढ़ाई जिससे वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। यह भव्य कलश यात्रा वैष्णो द्वार से शुरू होकर अग्रवाल धर्मसभा, भगत सिंह चौक, पांच मंदिर, दुर्गा मंदिर और मुख्य बाजार जैसे अनेक महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरी। यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्थानीय निवासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा का नेतृत्व पूज्यनीय संत कथा व्यास नारायण चौतन्य महाराज और महंत मनीष सलूजा ने किया। इस धार्मिक आयोजन के अवसर पर मंदिर महंत भजन प्रकाश अरोड़ा, श्याम खुराना, महापौर विकास शर्मा, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, संजय ठुकराल,भारत भूषण चुग, राजीव अरोड़ा, दीपक नारंग, सुखवीर सिंह, प्रमोद साहनी, गोविंद राय, गणेश राय, राजेंद्र पाल, अमन पाल, अजय पल, कमल पाल, रोहित पासी, सुरेंद्र गुंबर, कंचन, सुनीता अरोड़ा, सुखवीर मली, अनेजा,सतनाम सिंह,पवन डाबरा, कपिल, राजेश आनंद, नरेश घई, राजीव ग्रोवर,जगदीश अरोड़ा, जिगर गुंबर, लक्ष्य शर्मा,अंकित चौधरी, जितेंद्र, अशोक कुमार, गौरव गुंबर, सन्नी, हरीश प्रीति ग्रोवर, कवितासोढ़ी, राम जी, निशा, गगन गुंबर, मन्नू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस आयोजन ने क्षेत्र के लोगों में भक्ति की भावना को और भी मजबूत किया।

रेलवे भूमि के प्रभावित परिवारों ने मेयर से लगाई गुहार

हल्द्वानी। रेलवे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जद में आ रहे बनभूलपुरा क्षेत्र के इंदिरानगर में रह रहे करीब 250 परिवारों ने अपने भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से पुनर्वास की मांग की है। इस संबंध में इंदिरा नगर पुनर्वास कल्याण समिति के तत्वावधान में निवासियों का एक शिष्टमंडल मेयर गजराज सिंह बिष्ट और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। समिति के अध्यक्ष आनंद केसरवानी ने बताया कि इंदिरानगर क्षेत्र में रेलवे की अतिक्रमण भूमि पर लंबे समय से करीब ढाई सौ परिवार निवास कर रहे हैं। इन परिवारों में अधिकांश लोग आर्थिक रूप से कमजोर और ओबीसी वर्ग से जुड़े हैं, जो वर्षों से यहां रहकर अपने परिवारों का भरण–पोषण कर रहे हैं।शिष्टमंडल ने मांग की कि संभावित कार्रवाई से प्रभावित होने वाले सभी परिवारों के लिए उचित स्थान पर एक साथ पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। साथ ही परिवारों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे नए स्थान पर बसकर अपने जीवन और आजीविका को फिर से व्यवस्थित कर सकें।प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर संभव सहायता और समाधान के प्रयास किए जाएंगे, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। इस दौरान राज्य मंत्री दिनेश आर्य, हरिमोहन अरोड़ा, ओबीसी जिलाध्यक्ष नन्हें कश्यप, एससी जिलाध्यक्ष रविंद्र बाली, विनोद जायसवाल, शक्ति केंद्र संयोजक अरविंद केसरवानी, सीमा राठौर, विमला साहू सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।

स्मैक की तस्करी करता एक गिरफ्तार

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। बनभूलपुरा कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अवैध स्मैक की तस्करी करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार दिनेश सिंह फर्त्याल प्रभारी निरीक्षक बनभूलपुरा के नेतृत्व में नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करने व नशे की प्रवृति पर रोकथाम लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान संदिग्ध रूप से घूम रहे एक युवक को गोसिया मस्जिद के पीछे गली इन्द्रानगर से पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम पता रिजवान अंसारी उर्फ मंत्री पुत्र वसरूद्दीन अंसारी निवासी मौहम्मदी मस्जिद के बराबर गली इन्द्रानगर, बनभूलपुरा बताया। तलाशी ले पर उसके पास से कुल 32.13 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने बरामद स्मैक कब्जे में लेकर रिजवान को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक जगवीर सिंह, कांस्टेबल दिलशाद अहमद, सुच्चा सिंह व सुनील कुमार शामिल थे।

साहबजादे चौक पर हटाया अतिक्रमण

गदरपुर(उद संवाददाता)। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल तथा जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में तहसील गदरपुर अंतर्गत महतोष चौकी के पास स्थित साहबजादे चौक पर लोक निर्माण विभाग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई।प्रशासन द्वारा विगत दिनों उक्त स्थल पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था। कार्रवाई के दिन अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा प्रारंभ में विरोध किया गया, जिसके बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच वार्ता हुई। वार्ता के दौरान अतिक्रमणकर्ताओं ने स्वयं ही अतिक्रमण हटाने के लिए उपजिलाधिकारी रिचा सिंह गदरपुर से चार दिन का समय देने का अनुरोध किया।प्रशासन द्वारा निर्धारित समय दिए जाने के बाद अतिक्रमणकर्ताओं ने स्वयं ही लोक निर्माण विभाग की भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया।

विधायक शिव ने बंग भवन का निर्माण शीघ्र शुरू करने की उठाई मांग

रूद्रपुर। मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल बंगाली संस्कृति को समर्पित बंग भवन के निर्माण हेतु विधायक शिव अरोरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान मुलाकात कर वार्ता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक को आश्वस्त किया कि शीघ्र अति शीघ्र इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। विधायक शिव अरोरा ने मुख्यमंत्री को सौंपे पत्र में अवगत कराया कि रुद्रपुर को लघु भारत के नाम से जाना जाता है जहाँ हर जाति, भाषा और वर्ग का समाज निवास करता है।उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि भारत माता के विभाजन के बाद पूर्व पाकिस्तान से इस्लामिक कट्टरपंथियों के अत्याचार व यातनाओं को सहकर बंगाली समाज अपने धर्म की रक्षा हेतु अपने ही देश भारत में शरणार्थी होने को मजबूर हुआ था। जनपद में बंगाली समाज आजादी के बाद से ही काफी बड़ी संख्या में निवास करता है जिसने तराई के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विधायक शिव अरोरा ने बताया कि 14 अगस्त 2023 को आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उनके अनुरोध पर बंगाली समाज के श्रेष्ठ इतिहास एवं संस्कृति को समर्पित बंग भवन निर्माण को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया गया था, किन्तु अब तक इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।विधायक शिव अरोरा ने मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन किया कि तराई के विकास में अहम भूमिका निभा रहे बंगाली समाज के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल बंग भवन निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द कार्यवाही का भरोसा दिलाया है।

महापौर ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को किया सम्मानित

रुद्रपुर(उद संवाददाता)। नगर निगम परिसर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान समारोह में महापौर विकास शर्मा ने नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दर्जनों महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों और स्वरोजगार के क्षेत्र में मिसाल पेश करने के लिए प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। इस दौरान महापौर ने घोषणा की कि नगर निगम जल्द ही निजी कंपनियों के सहयोग से स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक नया ब्रांड तैयार करेगा। महापौर विकास शर्मा ने महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि रुद्रपुर की बहनों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों ने अपनी गुणवत्ता के दम पर राष्ट्रपति भवन तक अपनी धमक दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में 'हाउस ऑफ हिमालयाज' की तर्ज पर कुमाऊं का अपना एक विशिष्ट ब्रांड विकसित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री से वार्ता कर सहमति प्राप्त कर ली गई है। इस नई पहल के तहत महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रोफेशनल पैकेजिंग की जाएगी और निजी कंपनियों के सहयोग से उन्हें बड़े बाजारों में उतारा जाएगा। इससे न केवल महिलाओं की आय में वृद्धि होगी, बल्कि स्वरोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। महापौर ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी नीतियों के कारण देश की लाखों महिलाएं 'लखपति दीदी' बनकर उभरी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उत्तराखंड की मातृशक्ति आज आत्मनिर्भर बन रही है और समाज व परिवार को नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में नगर निगम भी लगातार बहनों को लखपति दीदी बनाने के लिए प्रयासरत है। मातृ शक्ति के उत्थान के लिए नगर निगम आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कार्यक्रम में नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष रेनू शर्मा, सचिव मधुलिका वर्मा और कोषाध्यक्ष पुष्पा बजेठा सहित बड़ी संख्या में महिलाओं को उनके समर्पण के लिए मंच पर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाली प्रमुख महिलाओं में हीरा पांडे, गीता देवी, शोभा देवी, नीलू बिष्ट, ममता आर्या, अनिता रानी, अनीता देवी, संगीता रावत, नीमा बिष्ट, प्रियंका आर्य, गीता उप्रेती, सुनीता देवी, प्रिया आर्या, रंजना सक्सेना, दीपा पहाड़ी, ममता नेगी, तारा जोशी, मनीषा, विनीता लखेड़ा, सपना रावत, माया देवी, पुष्पा कोहली, पार्वती भंडारी, स्नेहलता, अर्चना, अंजू, नीलम और कल्पना रावत आदि शामिल रहीं। इस अवसर पर बिट्टू शर्मा, पार्षद पवन राणा, विजय तोमर, सिटी मिशन मैनेजर मनोज कुमार सहित नगर निगम के अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

उत्तरांचल दर्पण सम्पादकीय

सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

दूषित पेयजल की चुनौती

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिस दौर में विज्ञान और तकनीक के मामले में नई ऊंचाइयां छूने का दावा किया जा रहा है, उसमें आज भी करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देश में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराए जा रहे पीने योग्य नल-जल की सुविधा के तिहत्तर फीसद दूषित नमूनों पर उपचारात्मक उपाय नहीं हो पाया। यानी देश में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, जिन्हें आज भी स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। सवाल है कि विकास की यह कौन-सी दिशा है, जिसमें पीने के साफ पानी की अनुपलब्धता से जुड़ी समस्या की इस हद तक अनदेखी की जा रही है कि आज यह व्यापक संकट का एक बड़ा कारण बनता दिख रहा है।राज्यों की भागीदारी से वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल मुहैया कराने का कार्यक्रम शुरू किया गया। मगर देश भर में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रबंधन में जिस स्तर की कोताही बरती जा रही है, कहीं वह आने वाले समय में एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती की शक्ल में न सामने आए।गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 में जल जीवन मिशन के तहत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की जांच के लिए चौंतीस राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से आए पानी के नमूनों की जांच की गई। जांच के बाद दूषित पाए गए कुल नमूनों में से केवल 26.31 फीसद पर ही उपचारात्मक उपाय किए जा सके।दरअसल, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों के घरों तक पहुंचाए जा रहे पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पेयजल के नमूने को संग्रह कर उनकी जांच की जाती है। जांच में अगर कहीं का पानी दूषित पाया जाता है, तो वहां जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाती है। अव्वल तो सवाल यह है कि पेयजल को स्वच्छ रखने के लिए क्या किया गया। फिर अगर कुल दूषित नमूनों में से तिहत्तर फीसद पर उपचारात्मक उपाय भी नहीं किए जा सके, तो क्या इसके लिए जिम्मेदारी तय की गई? क्या ऐसी ही लापरवाही की वजह से शहरों-महानगरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में लोगों के घरों तक पहुंचाए जाने वाले पेयजल के दूषित होने की समस्या और ज्यादा नहीं बढ़ती जा रही है? यह छिपा नहीं है कि आज देश के कई हिस्सों में लोग गंदा पानी पीने और उससे उपजी बीमारियों की चुनौती का सामना करने को मजबूर हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब देश भर में सबसे स्वच्छ माने जाने वाले शहर इंदौर में दूषित पेयजल के सेवन की वजह पंद्रह लोगों की मौत और कई लोगों के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की खबर देश भर में चिंता का कारण बनी थी। मगर इंदौर कोई अकेला शहर नहीं है, जहां पेयजल खतरनाक स्तर तक दूषित हो गया। देश के अलग-अलग हिस्से से आए दिन गंदा पानी घरों तक पहुंचने या इसकी वजह से लोगों के बीमार पड़ने की खबरें आती रहती हैं। मगर शायद ही कभी पेयजल और सीवर के पाइप को सुरक्षित दूरी पर रखने की योजना पर ठोस तरीके से काम किया गया।पीने से लेकर खाना पकाने और नहाने जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जिस पानी का उपयोग किया जाता है, उसका अधिकांश हिस्सा भूजल से आता है। अक्सर भूजल में आर्सेनिक, अमोनिया या अन्य जोखिम वाले तत्त्वों के बढ़ते जाने की रपट आती हैं। मगर इससे इतर हर घर जल अभियान के तहत जिस स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का दावा किया जाता है, अगर वह भी दूषित है, तो आखिर सरकार इस मोर्चे पर क्या कर रही है।

'महिला आयोग आपके द्वार' के तहत जनसुनवाई कार्यक्रम संपन्न

महिलाओं की शिकायतों पर त्वरित जांच कर कार्रवाई हेतु पुलिस विभाग को भेजे गए प्रकरण

नैनीताल (उद संवाददाता)। राज्य सरकार और महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा तथा उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। महिला आयोग उन महिलाओं को जो अपनी शिकायतों को लेकर आयोग तक नहीं पंहुच पाती हैं उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु महिला आयोग उनके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जनपद में आगामी 13 मार्च तक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर समस्याओं का निस्तारण कराया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को नैनीताल स्थित राज्य अतिथि गृह सभागार में महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन कराया गया जनसुनवाई में आयोग के समक्ष कुल 8 प्रकरण प्राप्त हुए। इन शिकायतों में मुख्य रूप से घरेलू हिंसा , महिला उत्पीड़न,संपत्ति विवाद, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रताड़ित किया जाना, घरेलू उत्पीड़न से संबंधित थी सभी शिकायतों को सुनते हुए महिला आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सायरा बानो ने कहा कि महिला आयोग हमेशा ही महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए खड़ा है पीड़ित महिला को अवश्य लाभ व न्याय मिलेगा । उन्होंने कहा कि आज की सुनवाई में जो भी यह आठ प्रकरण प्राप्त हुए हैं वह संबंधित सभी प्रकारण पुलिस विभाग से संबंधित हैं, इस संबंध में उन्होंने पुलिस विभाग को त्वरित जांच

करते हुए कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। उन्होंने कहा कि महिला आयोग का जनता स्तर पर जनसुनवाई कार्यक्रम का उद्देश्य ही महिलाओं का दर्द सुनना है उनकी समस्याओं का समाधान करना है उन्होंने कहा कि महिला आयोग के समक्ष जो भी शिकायत आज प्राप्त हुई हैं उन पर पुलिस विभाग त्वरित जांच करते हुए कार्रवाई करें। कहा कि जिन मामलों में दो पक्ष हैं,दोनों पक्षों को बुलाकर व सुनकर जांच करते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने महिलाओं से अपील की, कि किसी भी प्रकार की घटना या समस्या की जानकारी निशुल्क दूरभाष नंबर 112 पर दें। साथ ही गौरा शक्ति ऐप डाउनलोड करने तथा आयोग के दूरभाष नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग द्वारा पारिवारिक विवादों के समाधान और महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 13 जनपदों में 13 मार्च, 2026 तक महिला जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य अतिथि गृह नैनीताल में आयोजित महिला जनसुनवाई कार्यक्रम में कुल 8 मामलों की सुनवाई हुई, सभी प्रकरणों में पुलिस विभाग की ओर से कार्यवाही होनी थी इस संबंध में पुलिस विभाग को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। इस अवसर पर महिला आयोग की सदस्य उर्मिला जोशी, कंचन कश्यप, पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्रा, अपर जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी,उप जिला अधिकारी नवाजिश खालिक, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलेखा बिष्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, महिला आयोग के प्रतिनिधि व शिकायतकर्ता उपस्थित रहे।

उत्पाद विकास और मानकों की भूमिका पर राष्ट्रीय सेमिनार

पंतनगर (उद संवाददाता)। विश्वविद्यालय के सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय में उत्पाद विकास, गुणवत्ता एवं सुरक्षा में मानकों की भूमिका विषय पर एक बहु-विषयक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार का आयोजन बीआईएस कम्युनिटी साइंस स्टूडेंट चौप्टर द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मानकों की भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि वर्तमान वैश्विक एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में उत्पादों की सफलता केवल उनके नवाचार और प्रदर्शन पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि स्थापित मानकों के अनुपालन पर भी आधारित होती है। मानक उत्पाद विकास की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाते हैं तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में गुणवत्ता, विश्वसनीयता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।इसके अतिरिक्त वक्ताओं ने कहा कि मानकों का पालन उद्योगों के नियमों को पूरा करने,

त्रुटियों को कम करने तथा उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने में भी सहायता प्रदान करता है। इस राष्ट्रीय सेमिनार में देशभर से शिक्षाविद, शोधकर्ता, उद्योग विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी, शोधार्थी तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने शोध कार्यों तथा विचारों को साझा किया। प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्रों को मौखिक एवं पोस्टर प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उत्कृष्ट प्रस्तुतियों का चयन मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया तथा उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किए गए। सेमिनार के अंतर्गत परिधान एवं वस्त्र मानक, उपभोक्ता संरक्षण एवं सुरक्षा मानक, सतत विकास से संबंधित मानक, खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण में मानकीकरण, खाद्य स्वच्छता एवं लेबलिंग मानक, संसाधन प्रबंधन के मानक तथा भारतीय बच्चों के विकासात्मक मूल्यांकन उपकरणों के मानकीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया।यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के कुलसचिव दीपा विनय के निर्देशन में आयोजित किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता अधिष्ठात्री, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय अल्का गोयल ने की। कार्यक्रम समन्वयक एसबी सिंह, संयोजक साक्षी तथा सह संयोजक नीतू डोभाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस सेमिनार ने सरकार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को सुदृढ़ बनाने तथा मानकीकरण के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

रूद्रपुर में एलपीजी की कमी से होटल-रेस्टोरेंट पर संकट : संजय

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और बढ़ते तनाव का असर अब रुद्रपुर में भी दिखाई देने लगा है। शहर की गैस एजेंसियों पर एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे आम लोगों में चिंता का माहौल बन गया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि यदि एक-दो दिन के भीतर एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो शहर के कई होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने बताया कि होटल और रेस्टोरेंट बंद होने से इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भोजन के लिए इन प्रतिष्ठानों पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट में बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं और यदि गैस आपूर्ति प्रभावित रही तो उनकी नौकरियों पर भी संकट खड़ा हो सकता है। संजय ने कहा कि पेट्रोलियम दानों (कच्चे माल) से अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम दानों के दाम रोज बढ़ने से रोजमर्रा की कई वस्तुओं के दामों में भी महंगाई का असर दिखाई पड़ सकता है। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति जल्द से जल्द सुचारु कराई जाए, ताकि आम जनता और व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उत्तराखंड की 'दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना' बनी मिसाल

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना' की सफलता की गूँज अब अन्य राज्यों में भी सुनाई देने लगी है। हाल ही में गुजरात में आयोजित सहकारी सम्मेलन में इस योजना की सराहना के बाद, गुजरात के पंचमहल जिला सहकारी बैंक लिमिटेड का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस मॉडल का अध्ययन करने उत्तराखंड पहुँचा। मंगलवार को बैंक के उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह उदे सिंह बारिया के नेतृत्व में आए इस प्रतिनिधिमंडल का उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के हल्द्वानी स्थित मुख्यालय में भव्य स्वागत किया गया। मुख्यालय पहुँचने पर बैंक के प्रबंध निदेशक प्रदीप मेहरोत्रा ने प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन किया और उन्हें प्रदेश के सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति, कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता

किसान कल्याण योजना' पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसके अंतर्गत किसानों को 1 लाख तक का अल्पकालीन तथा 3 लाख तक का मध्यकालीन ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने इस योजना को बेहद प्रभावी और किसान हितैषी बताते हुए इसे अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल करार दिया। चर्चा के दौरान भारत दर्शन ऋण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक ब्याज रहित ऋण देने की व्यवस्था पर भी मंथन किया गया। शैक्षिक भ्रमण के इसी क्रम में प्रतिनिधि मंडल ने नैनीताल जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के मुख्यालय का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली और ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को करीब से समझा। कार्यक्रम में सहायक महाप्रबंधक (आईटी) नेहा कान्त ने सहकारी बैंकों में डिजिटल पहलों पर प्रस्तुतीकरण दिया, जबकि महाप्रबंधक सुरेश सिंह नेपलच्याल ने गुजरात के सहकारिता मॉडल के अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन सहायक महाप्रबंधक धीर सिंह द्वारा किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के दौरों से दोनों राज्यों के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान होगा, जिससे डिजिटलीकरण और ग्रामीण बैंकिंग विस्तार को नई गति मिलेगी।

शिक्षकों ने लोहा चुरा रहे दो लोगों को रंगे हाथ दबोचा

सितारगंज(उद संवाददाता)। टीचर्स कॉलोनी में खाली पड़े आवास में पानी की टंकियां और खिड़कियों के ग्रिल काटकर लोहा चुरा रहें दो लोगों को शिक्षकों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। शिक्षकों ने दोनों आरोपियों को पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जीआईसी सितारगंज के प्रभारी प्रधानाचार्य विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि 9 मार्च की शाम करीब छह बजे शिक्षक कॉलोनी के खाली आवासों से कुछ काटने की आवाज आ रही थी। शक होने पर वह अपने साथी शिक्षक डॉ. धर्मेंद्र नाथ चौबे, चंदन सिंह डसीला, हरिशंकर याज्ञिक, संजय कुमार शुक्ला, नेहा ओझा और उमेश पांडे के साथ खाली पड़े आवासों की तरफ गए। वहां देखा कि दो लोग पानी की टंकी और खिड़की का ग्रिल काटकर लोहा इकट्ठा कर रहे हैं। इस पर शिक्षकों ने दोनों को दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम शाहवेज निवासी अमरिया (पीलीभीत) और गुरदीप सिंह निवासी गांव मुंडलिया, अमरिया (पीलीभीत) बताया। शिक्षकों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहीं, मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।

अल्मोड़ा जिला न्यायालय को फिर मिली उड़ाने की धमकी

अल्मोड़ा(उद संवाददाता)। जिला न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से मंगलवार को न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। धमकी भरा ई-मेल मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। जानकारी के अनुसार, सोमवार को जिला न्यायाधीश के आधिकारिक ई-मेल पर न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस सूचना के बाद मंगलवार सुबह पुलिस, खुफिया विभाग, एसडीआरएफ और बम निरोधक दस्ते की संयुक्त टीम न्यायालय परिसर पहुंची और सुरक्षा जांच शुरू की। टीम ने न्यायालय भवन के सभी कोर्ट कक्षों, रिकॉर्ड कक्ष, पार्किंग स्थल और आसपास के सार्वजनिक स्थानों की बारीकी से जांच की। न्यायालय में आने-जाने वाले लोगों की सघन तलाशी ली गई और परिसर में खड़े वाहनों की भी जांच की गई। इसके साथ ही परिसर में अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की अपील की गई तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई। सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद यह धमकी भी निराधार पाई गई, हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी वाले मेल के बाद संयुक्त टीम ने न्यायालय परिसर की गहन छानबीन की है।

जगदीश
कलर लैब
टंडन फोटो स्टूडियो
पासपोर्ट फोटो तुरन्त प्राप्त करें
जनरेटर सुविधा भी उपलब्ध है।
मोबाइल, थिए, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, सीडी आदि डिजिटल कार्य तुरन्त बनवायें।
काशीपुर बाईपास रोड,
गुरुनानक कन्या इण्टर कालेज के सामने गली में, रुद्रपुर
E-mail: jagdishcolourlab@gmail.com
Web: jagdishcolourlab.com
05944-246817

रसोई गैस की कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

गोदामों के निरीक्षण और स्टॉक मिलान के निर्देश

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। घरेलू गैस (एलपीजी) सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को तहसील परिसर स्थित एनआईसी कक्ष में अपर जिलाधिकारी प्रशासन विवेक राय की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि जनपद में रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है और पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए आम जनता को किसी भी प्रकार से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि मांग के अनुरूप गैस कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने गैस की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से जनपद के सभी गैस वितरकों और एरिया प्रबंधकों के साथ-साथ नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी और खाद्य आपूर्ति विभाग को अपने-अपने क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि गैस का वितरण केवल बुकिंग के उपरांत डीएससी कोड और ओटीपी के आधार पर ही सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, नियमानुसार 25 दिनों के अंतराल के बाद ही सिलेंडर की आपूर्ति की जाए ताकि अनावश्यक स्टॉकिंग को रोका जा सके। बैठक में एडीएम ने अधिकारियों को विशेष रूप से घटतौली और रिफिलिंग जैसे अवैध कार्यों पर पैनी नजर रखने और दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने को कहा। नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को निर्देशित किया गया कि वे नगर के भीतर स्थित सभी गोदामों का औचक निरीक्षण कर स्टॉक का भौतिक मिलान करें। उन्होंने जनता से अपील की कि रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है, अत: किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और न ही अनावश्यक भंडारण करें। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी एपी बाजपेई, महाप्रबंधक केएमवीएन विजय नाथ शुक्ल, जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन सहित सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक और विभिन्न गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जनपद के न्यायालयों में 14 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में 14 मार्च 2026 द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेन्द्र कुमार सागर ने बताया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर द्वारा जनपद में 14 मार्च को प्रात: 10 बजे से सांय 05 बजे तक रूद्रपुर स्थित जिला न्यायालय सहित वाह्य स्थित दीवानी न्यायालयों काशीपुर, खटीमा, बाजपुर, जसपुर, सितारगंज एवं किच्छा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेन्द्र कुमार सागर ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के वादों का निस्तारण किया जाएगा जिनमें मुख्य रूप से भरण पोषण, धन वसूली, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, अपराधिक शमनीय व सिविल मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित शमनीय प्रकृतिक के आपराधिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, वैवाहिक मामले तलाक को छोड़कर, भूमि अधिग्रहण, भुगतान व भत्तों से सम्बन्धित सर्विस के मामले, जिला न्यायालय में लंबित राजस्व वाद, मोटर वाहन अधिनियम के शमनीय अपराधों के चालान और किरायेदारी व व्यादेश जैसे सिविल मामलों का निस्तारण किया जाएगा।उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति अपने वादों का निस्तारण करवाना चाहते हैं, वे सम्बन्धित न्यायालय में किसी भी कार्य दिवस में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने वादों को नियत करवा सकते हैं। इसके अलावा जिला न्यायालय परिसर में स्थित एडीआर केन्द्र रूद्रपुर में भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्प डेस्क नंबर 9411531449 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्री लिटिगेशन के वादों का निस्तारण किया जाएगा

नहीं रहे सुप्रसिद्ध लोकगायक दीवान कनवाल

अल्मोड़ा(उद संवाददाता)। सुविख्यात लोकगीत गायकों में सुमार तथा अपनी जादुई कर्णप्रिय गायन प्रतिभा से जनमानस का दिल जीतने वाले संस्कृतिकर्मी दीवान कनवाल का निधन हो गया है। वह करीब 65 वर्ष के थे।दीवान कनवाल उर्फ 'दीवान दा' अपने गीतों की मिठास और सादगी से लोगों के दिलों में बसते थे। उनके निधन से अल्मोड़ा समेत प्रदेशभर में शोक की लहर है। उनके निधन का समाचार सुनने के बाद हर कोई इस महान लोकगायक को श्रद्धांजलि दे रहा है।जिला मुख्यालय स्थित खत्याड़ी गांव निवासी दीवान कनवाल पिछले कुछ समय से अस्वस्थ्य चल रहे थे। हल्द्वानी के एक हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा था। ऑपरेशन के बाद कुछ दिन पहले ही वह अपने घर लौटे थे। बुधवार सुबह उन्होंने अपने आवास में अंतिम सांस ली।दीवान कनवाल अपने पीछे अपनी वयोवृद्ध माता, दो विवाहित पुत्रों, दो पुत्रियों को रोता बिलखता छोड़ गए

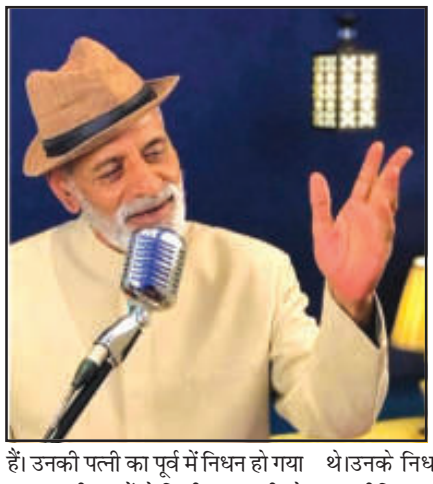

हैं। उनकी पत्नी का पूर्व में निधन हो गया था। स्थानीयजनों से मिली जानकारी के मुताबिक स्व. कनवाल की अंतिम यात्रा बुधवार दोपहर या अपराह्न में स्थानीय बेतालेश्वर घाट के लिए प्रस्थान करेगी।दीवान कनवाल के, 'दाज्यु हमार जवाई रिषे ग्ये, आज कुछ मैत जा कस भिड़े कुनई पंडित ज्यू कस करछा ब्या. ह्यू भरी डाना समेत कई आंचलिक कुमांऊनी बोली-भाषा के गाने बहुत हिट हुए। साथ ही लोगों द्वारा खूब गाए-बजाए गए। करीब 35 वर्षों से अधिक समय तक अपनी गायकी से उन्होंने लोगों का दिल जीता। सभी सांस्कृतिक आयोजनों में वें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे।उनके निधन पर लोक कलाकारों, राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत कई लोगों ने शोक जताया है।

प्रेस समाज और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण सेतु: डीएम

अल्मोड़ा(उद संवाददाता)। अल्मोड़ा में मंगलवार का उत्तराखंड प्रेस क्लब अल्मोड़ा की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान डीएम अंशुल सिंह ने सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रेस क्लब कार्यालय में आयोजित समारोह में डीएम ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि प्रेस समाज और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है तथा जनहित के मुद्दों को सकारात्मक ढंग से सामने लाकर व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम योगदान देता है। कहा कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को सही, निष्पक्ष और तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध कराना है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रेस क्लब अल्मोड़ा की नई कार्यकारिणी पत्रकारिता के मूल्यों को बनाए रखते हुए समाजहित में कार्य करेगी और जनपद के विकास से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से सामने लाएगी। वहीं, नव निर्वाचित अध्यक्ष जगदीश चंद्र जोशी ने कहा कि प्रेस क्लब अपने दायित्व में खरा उतरने की पूरी

कोशिश करेगा। उन्होंने मुख्य अतिथि डीएम अंशुल सिंह का आभार जताते हुए कहा कि युवा एवं ऊर्जावान डीएम के सहयोग से प्रेस क्लब की प्रगति में अपेक्षित गति आएगी। संचालन कार्यालय उपसचिव कपिल मल्होत्रा एवं सचिव अशोक पांडे ने किया। उत्तराखंड प्रेस क्लब अल्मोड़ा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगदीश चंद्र जोशी, उपाध्यक्ष कमलेश कनवाल, सचिव अशोक पांडे, उप सचिव संस्था, मोहित अधिकारी, उप सचिव कार्यालय कपिल मल्होत्रा, संप्रेक्षक हरीश भंडारी, कोषाध्यक्ष संतोष बिष्ट, विधिक सलाहकार रोहित कार्की, संजय अग्रवाल, सदस्य कार्यकारिणी किशन चंद्र जोशी, हिमांशु लटवाल, शिवराज सिंह कपकोटी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली।

पेज एक का शेष...

हरीश राणा को ...पोषण के लिए उसके पेट में पीईजी ट्यूब लगाई गई थी। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, इतने लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उसके शरीर पर बड़े-बड़े बेड सोर्स (जख्म) हो गए थे और विशेषज्ञ डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया था कि अब उसके स्वास्थ्य में सुधार की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है। अपने बेटे की इस नारकीय स्थिति और घुट-घुट कर जीने की विवशता को देखते हुए उसके पिता ने अंतत: न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एम्स के विशेषज्ञों का एक विशेष मेडिकल बोर्ड गठित किया। बोर्ड ने सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट में कहा कि हरीश का इलाज जारी रखना केवल उसकी जैविक उपस्थिति को लंबा खींचना है, जिससे उसे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इस रिपोर्ट पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी इंसान को इस तरह की स्थिति में लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही भविष्य के लिए भी कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने आदेश दिया कि हरीश को दी जा रही सभी जीवन-रक्षक सुविधाएं, जिनमें चिकित्सकीय पोषण भी शामिल है, उन्हें तुरंत प्रभाव से पूरी गरिमा के साथ हटा दिया जाए। इसके साथ ही एम्स को निर्देशित किया गया है कि वह हरीश को अपने पेलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती कर इस पूरी प्रक्रिया को सम्मानजनक ढंग से पूरा करे। अदालत ने केंद्र सरकार से यह भी सिफारिश की है कि पैसिव यूथेनेशिया के भविष्य में आने वाले मामलों के लिए एक व्यापक कानून बनाया जाए। इसके अलावा, सभी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के लिए डॉक्टरों का एक पैनल तैयार रखें ताकि भविष्य में ऐसे परिवारों को लंबी कानूनी पेचीदगियों से न जूझना पड़े। यह फैसला न केवल हरीश के लिए मुक्ति का मार्ग है, बल्कि देश में 'राइट टू डाई विद डिग्निटी' के सिद्धांत को धरातल पर उतारने वाला पहला कदम भी है।

खाड़ी युद्ध की तपिश...कर दिया है। अब कोई भी घरेलू उपभोक्ता 25 दिन की समय सीमा पूरी होने से पहले अगला सिलेंडर बुक नहीं करा सकता है। इस पाबंदी ने विशेष रूप से उन मध्यमवर्गीय और बड़े परिवारों के सामने संकट खड़ा कर दिया है जिनकी खपत अधिक है। सरकार का तर्क है कि इस कदम से अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगेगी, लेकिन हकीकत में आम उपभोक्ता इस गहरे डर में जी रहा है कि यदि वर्तमान सिलेंडर बीच में ही खत्म हो गया तो अगला सिलेंडर समय पर मिल पाएगा या नहीं। इसी भारी अनिश्चितता और भय के चलते रूद्रपुर सहित पूरे कुमाऊं क्षेत्र की गैस एजेंसियों पर सुबह पांच बजे से ही लोगों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं, जहां लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। खाड़ी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में जो उछाल आया है, उससे भविष्य में घरेलू कीमतों में भारी वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। आर्थिक जानकारों का मानना है कि यदि यह वैश्विक तनाव और युद्ध जल्द समाप्त नहीं हुआ, तो इसका खामियाजा देश के कृषि, परिवहन और तमाम औद्योगिक क्षेत्रों को अगले कई महीनों तक भुगतना पड़ सकता है। गैस वितरण केंद्रों पर किल्लत का आलम यह है कि घंटों लाइन में खड़े रहने और अधिकारियों से मिन्नतें करने के बाद भी कई उपभोक्ताओं को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ रहा है। वितरण व्यवस्था में आए इस असंतुलन ने सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर दबाव बढ़ा दिया है।

गैस सिलेंडर जब्त...जिन लोगों के सिलेंडर जब्त किये गये है उन्हें रसीद भी दी गई है। यदि जांच के बाद सिलेंडरों की कालाबाजारी या अवैध रिफ्लिंग होना नहीं पाया गया तो सिलेंडर वापस कर दिये जायेंगे। हंगामे के बीच दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक चली कहासुनी के बाद उपभोक्ता मायूस लौट गये। इस दौरान एजेन्सी के समक्ष हंगामा होने से लोगों की भीड़ भी लग गई।

होटल रेस्टोरेंट...हो रही है क्योंकि यदि होटल और रेस्टोरेंट समय पर भोजन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तो इसका सीधा नकारात्मक असर देवभूमि आने वाले पर्यटकों पर पड़ेगा। व्यापारियों का स्पष्ट कहना है कि यदि सरकार ने जल्द ही कमर्शियल आपूर्ति को सुचारू नहीं किया, तो इस महंगाई के दौर में हजारों लोगों का रोजगार छिनना लगभग तय है।

प्रशासन ने की ...करें और ईंधन का उपयोग अत्यंत संयमित ढंग से करें। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विभाग अब उन तत्वों पर भी कड़ी नजर रख रहा है जो इस आपदा को अवसर में बदलकर मुनाफाखोरी और कालाबाजारी का प्रयास कर रहे हैं।

सत्र के तीसरे दिन.. पड़ी। सत्र के तीसरे दिन विधायी कार्यों की दृष्टि से भी भारी गहमागहमी रहने वाली है। आज सदन पटल पर कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक और अध्यादेश चर्चा के बाद पारित किए जाने के लिए रखे गए हैं। इनमें विशेष रूप से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक और उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक और निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक सहित कुल 11 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया जाना है। साथ ही समान नागरिक संहिता और जीएसटी से जुड़े महत्वपूर्ण अध्यादेशों को भी सदन की मंजूरी के लिए पेश किया गया है।

गैरसैण स्थायी राजधानी...जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर विधायक सुमित हृदयेश विधानसभा भवन परिसर में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सरकार पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया।

जंगल में महिला...लापता महिलाओं के रिकॉर्ड खंगाल रही है और हुलिए के आधार पर पहचान करने की कोशिश की जा रही है। शव मिलने के बाद से क्षेत्र के निवासियों में दहशत और असुरक्षा का माहौल है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका की पहचान के लिए सोशल मीडिया और आसपास के थानों की मदद ली जा रही है। शिनाख्त होने के बाद ही घटना की गुत्थी सुलझने की उम्मीद है। पुलिस इस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है।

गुंजन सुखीजा की ...किसानों को पौध बेचने की अनुमति दी जाए। इस पर उपजिलाधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा पौध नहीं जोती जाएगी और जिन किसानों ने पौध लगाई है, वे उसे निर्धारित क्षेत्रों के किसानों को बेच सकेंगे।बैठक के बाद गुंजन सुखीजा ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी मेहनत की कमाई को इस तरह नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा पौध जोतने की कार्यवाही से किसानों में रोष और आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो और वे नियमों का पालन करते हुए अपनी पौध बेच सकें। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सुरेश खुराना, भाजपा नेता भोला शर्मा, प्रधान विकास राय, बलजीत सिंह, प्रणव विश्वास सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

तलवार की नोक...लामाखेड़ा निवासी अरुण सिंह ने आरोप लगाया 10 मार्च की शाम वह बाइक से पेट्रोल भराने ओढली गया था। रास्ते में गुरजीत सिंह और उसके साथी ने जबरन रोककर उसके साथ गाली गलौज की इस दौरान हमलावरों ने उसकी गर्दन पर तलवार रखकर बाइक लूट ली। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है ।

विधायक बेहड़ ने सदन में उठाया आवारा पशुओं का मुद्दा

दो महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण की रखी मांग

देहरादून/किच्छा (उद संवाददाता)। विधानसभा सत्र के दौरान किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने प्रदेश में गहराती आवारा और छुट्टा पशुओं की समस्या को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित किया। नियम-300 के अंतर्गत इस गंभीर जनहित के विषय को उठाते हुए विधायक बेहड़ ने कहा कि किच्छा सहित पूरे उत्तराखंड में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर बेखौफ घूम रहे आवारा पशु आम जनमानस के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस समस्या के स्थाई और ठोस समाधान के लिए प्रभावी नीति बनाने की मांग की।विधायक बेहड़ ने सदन को अवगत कराया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था इन पशुओं के कारण चरमरा गई है। विशेष रूप से रात्रि के समय सड़कों के बीचों-बीच पशुओं के जमावड़े से आए दिन भीषण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें कई लोग

अपनी जान गंवा चुके हैं और दर्जनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने किसानों का पक्ष रखते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशु रात के अंधेरे में खड़ी फसलों को तहस-नहस कर रहे हैं, जिससे काश्तकारों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अपनी फसल बचाने के लिए किसान कड़ाके की ठंड और असुरक्षित माहौल में रात-भर खेतों में पहरा देने को मजबूर हैं।सदन में अपनी बात रखने के बाद विधायक तिलक राज बेहड़ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से व्यक्तिगत मुलाकात कर किच्छा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र की दो प्रमुख सड़कों ख़ अटरिया-नगला रोड तथा शिमला पिस्तौर-कुर्रेय्या रोड के अविलंब निर्माण की पुरजोर मांग उठाई। विधायक ने मुख्यमंत्री को बताया कि इन सड़कों की जर्जर हालत के कारण हजारों ग्रामीणों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने विधायक की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक स्वीकृति और त्वरित कार्यवाही के निर्देश देने का आश्वासन दिया है।

संस्थापक-स्व० हरनामदास सुखीजा एवं स्व०तिलकराज सुखीजा
स्वामित्वाधिकारी,प्रकाशक एवं मुद्रक परमपाल सुखीजा द्वारा उत्तरांचल दर्पण पब्लिकेशन्स, श्याम टाकीज रोड,रुद्रपुर,ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड)से मुद्रित एवं प्रकाशित
सम्पादक- परमपाल सुखीजा
आरएनआई नं.: UTTHIN/2002/8732 समस्त विवाद रूद्रपुर न्यायालय के अधीन होंगे।
E-mail-darpan.rdr@gmail.com,www.uttaranchaldarpan.in
फोन-245886(O)245701(Fax),9897427585,9897427586(Mob.)

कमिश्नर ने किया विकास प्राधिकरण कार्यालय का निरीक्षण

जन समस्याओं और पुराने वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के दिए निर्देश

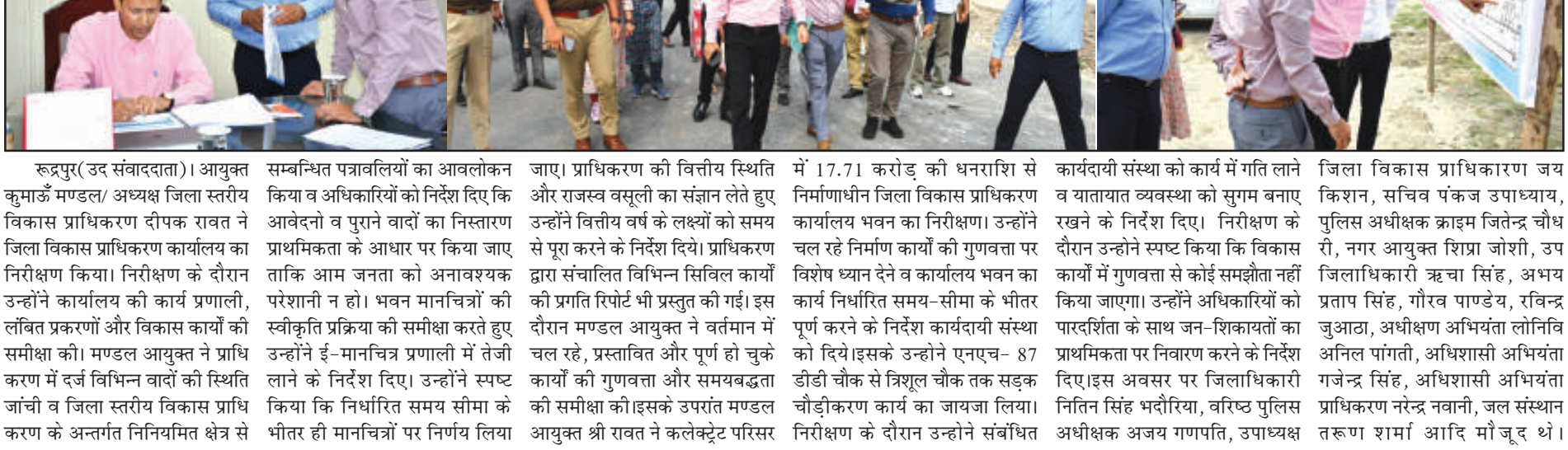

रूद्रपुर(उद संवाददाता)। आयुक्त कुमाऊँ मण्डल/ अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्य प्रणाली, लंबित प्रकरणों और विकास कार्यों की समीक्षा की। मण्डल आयुक्त ने प्राधिकरण में दर्ज विभिन्न वादों की स्थिति जांची व जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत निनियमित क्षेत्र से सम्बन्धित पत्रावलियों का आवलोकन किया व अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदनो व पुराने वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानी न हो। भवन मानचित्रों की स्वीकृति प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उन्होंने ई-मानचित्र प्रणाली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ही मानचित्रों पर निर्णय लिया जाए। प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति और राजस्व वसूली का संज्ञान लेते हुए उन्होंने वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिये। प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न सिविल कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। इस दौरान मण्डल आयुक्त ने वर्तमान में चल रहे, प्रस्तावित और पूर्ण हो चुके कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता की समीक्षा की।इसके उपरांत मण्डल आयुक्त श्री रावत ने कलेक्ट्रेट परिसर में 17.71 करोड़ की धनराशि से निर्माणाधीन जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय भवन का निरीक्षण। उन्होंने चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने व कार्यालय भवन का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिये।इसके उन्होने एनएच- 87 डीडी चौक से त्रिशूल चौक तक सड़क चौड़ीकरण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होने संबंधित कार्यदायी संस्था को कार्य में गति लाने व यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ जन-शिकायतों का प्राथमिकता पर निवारण करने के निर्देश दिए।इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकारण जय किशन, सचिव पंकज उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक क्राइम जितेन्द्र चौधरी, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह, अभय प्रताप सिंह, गौरव पाण्डेय, रविन्द्र जुआठा, अधीक्षण अभियंता लोनिवि अनिल पांगती, अधिशासी अभियंता गजेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता प्राधिकरण नरेन्द्र नवानी, जल संस्थान तरूण शर्मा आदि मौजूद थे।

किच्छा की खुशहाली के लिए आनंदपुर हनुमान मंदिर में हुआ सुंदरकांड पाठ

किच्छा। पंतनगर किच्छा विधानसभा क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता अजय तिवारी द्वारा लिए गए 108 सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा पाठ के संकल्प के क्रम में 10 मार्च, मंगलवार को ग्राम आनंदपुर स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का एक और धार्मिक आयोजन संपन्न कराया गया।कार्यक्रम की शुरुआत श्रीराम, हनुमान जी और नीम करोली बाबा के जयघोष के साथ हुई। इस अवसर पर हनुमान मंदिर ग्राम आनंदपुर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और श्रद्धा भाव के साथ सुंदरकांड पाठ में सहभागिता कर क्षेत्र की शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सामूहिक पाठ और भक्ति भाव से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। सुंदरकांड पाठ के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीराम और बजरंगबली के जयकारों के साथ भजन-कीर्तन भी किए, जिससे वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। श्री तिवारी ने बताया कि 108 सुंदरकांड पाठ का यह क्रम आगे भी लगातार जारी रहेगा और पंतनगरख्किच्छा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नियमित रूप से इस प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते रहेंगे। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र में धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने वाला प्रयास बताया।

श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन वामन भगवान की लीला का सुंदर वर्णन

गदरपुर। श्री अद्वैत स्वरूप अनन्त आश्रम, गदरपुर में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा के चौथे दिन भगवान वामन अवतार की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया गया। कथा के दौरान संत त्याग पुरी जी महाराज ने भगवान वामन और राजा बलि की कथा का विस्तार से वर्णन करते हुए बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने वामन रूप धारण कर बालक के रूप में राजा बलि के पास पहुंचकर तीन पग भूमि का वरदान मांगा।उन्होंने बताया कि दानवीर राजा बलि अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। वामन भगवान ने पहले पग में धरती और पाताल को नाप लिया तथा दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। इसके बाद भगवान ने राजा बलि से तीसरा पग रखने के लिए स्थान पूछा। तब राजा बलि ने अपना शीश झुका दिया और भगवान ने तीसरा पग उनके सिर पर रखकर उनका प्रण पूर्ण कराया।कथा के दौरान भगवान वामन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

कथा में संत ध्यान पुरी जी तथा संत व्यास पुरी जी महाराज भी उपस्थित रहे।इस अवसर पर भक्त अशोक बजाज, विजय शर्मा, रामस्वरूप, सुरेंद्र मिंगलानी, अतुल मिंगलानी, देसराज, रमाकांत, चंदू कंबोज, केवल कृष्ण, सुदर्शन गुम्बर, विक्की, सुशील बजाज, अशोक मिंगलानी, राजकुमार मुंजाल, सीमा मिंगलानी, ममता, सरोजनी, राखी, रोजी, कृष्णा रानी, वीना मिंगलानी, शगुन मिंगलानी, ममता रानी सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे।

ठुकराल ने कमिश्नर के सामने उठाया भूमि धोखाधड़ी का मामला

ग्राम खानपुर में बिना बिक्री के भूमि को अकृषक घोषित कराने और पेट्रोल पंप लगाने का आरोप

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। रुद्रपुर दौरे पर आए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के नेतृत्व में पीड़ित पक्ष ने एक ज्ञापन सौंपकर ग्राम खानपुर में भूमि धोखाधड़ी और अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी भूमि को बिना किसी विक्रय के ही कागजों में हेरफेर कर अकृषक घोषित करा दिया गया है और अब उस पर जबरन पेट्रोल पंप लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर दीपक रावत ने जांच के उपरांत उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कुमाऊं आयुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में प्रार्थी नित्यानंद पुत्र संतोष, निवासी खानपुर पूर्व ने बताया कि उनकी खसरा संख्या-486ख और 539घ (कुल रकबा लगभग 1.125 हेक्टेयर) भूमि राजस्व अभिलेखों में उनके परिवार के नाम दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरबाज सिंह नामक व्यक्ति ने उनकी खसरा संख्या-539घ (रकबा 0.3380 हेक्टेयर) को कूटरचित तरीके से अकृषक (143) घोषित करा लिया है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि उन्होंने यह भूमि कभी किसी को विक्रय नहीं की, फिर भी धोखाधड़ी से दाखिल-खारिज करा लिया, जिसका कोई वैध साक्ष्य नहीं है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी अपनी बगल की भूमि (खसरा संख्या-539ग) की आड़ में पीड़ितों की जमीन पर अवैध रूप से मिट्टी भरान करवा रहा है और वहां पेट्रोल पंप स्थापित करने की फिराक में है। वर्तमान में यह मामला एसडीएम रुद्रपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ितों ने मांग की है कि जब तक न्यायालय में मामला लंबित है, तब तक वहां किसी भी प्रकार के निर्माण या मिट्टी डालने पर रोक लगाई जाए। साथ ही, यदि पेट्रोल पंप का लाइसेंस स्वीकृत हो गया है तो उसे तत्काल निरस्त किया जाए और नया लाइसेंस जारी न किया जाए। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कमिश्नर से इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि गरीब किसानोंकी भूमि पर इस तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नर दीपक रावत ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि वह इस संबंध में जिलाधिकारी और संबंधित तहसील प्रशासन से रिपोर्ट तलब कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।